प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

पीएमएवाई-जी : सम्मान का द्वार

ग्रामीण भारत के बेघर और गरीब लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति

घर की चाबी सम्मान, आत्मविश्वास, सुनिश्चित भविष्य, नई पहचान और बढ़ती संभावनाओं के द्वार खोलती है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के माननीय प्रधान मंत्री

विषय-सूची

प्रस्तावना		01
1.	अध्याय 1: पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में कमियां	03
2.	अध्याय 2: प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण – ग्रामीण गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना	08
3.	अध्याय 3: “आवास” से “घर”	13
4.	अध्याय 4: लाभार्थियों के निर्धारण का सुदृढ़ दृष्टिकोण	16
5.	अध्याय 5: गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर	18
6.	अध्याय 6: साक्ष्य आधारित निगरानी और प्रभाव का निर्धारण	23
7.	अध्याय 7 : कोविड-19 आपदा के दौरान अतिरिक्त प्रयास	27
8.	सफलता की कहानियां	29
9.	मीडिया गैलरी	34

लाभार्थी का नाम : अनिल (एमपी1935999)
गांव : मेधतल
ब्लॉक : बिछिया
जिला : मंडला
राज्य : मध्य प्रदेश

प्रस्तावना

"घर प्यारा घर" प्रत्येक व्यक्ति का सबसे पुराना सपना रहा है। जिनके पास बेहतर संसाधन हैं, वे अपना स्वयं का शानदार घर बना सकते हैं लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोग ये सपना साकार नहीं कर पाते हैं। करोड़ों लोगों ने मानवीय गरिमा से हीन दशाओं में झोपड़ियों में जीवन जीया है।

लगभग 70 वर्षों से इस परिस्थिति में मामूली सुधार ही हुआ है। बढ़ती आबादी के साथ झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की संख्या बढ़ती रही है।

मई, 2014 में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की जीवन-दशा में बदलाव के लिए पक्के मकानों का निर्माण करके उन्हें वे मकान उपलब्ध कराने के प्रधान मंत्री जी के सपने और इस सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की परिणति प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण और शहरी के शुभारंभ के रूप में हुई।

हमने इस पुस्तिका में प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के आरंभ, विकास, विशेषताओं इत्यादि की शानदार कहानी और ग्रामीण गरीबों के जीवन में आए अभूतपूर्व बदलाव का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

लाभार्थी का नाम : रामेश्वर महतो (जेएच1618964)

ग्राम : तरनतारन मधुबनी

प्रखंड : चंद्रपुरा

जिला : बोकारो

राज्य : झारखंड

अध्याय 1

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना में कमियां

आवास को सार्वभौमिक रूप से एक बुनियादी मानवीय आश्वयकता माना जाता है। ग्रामीण आवास की कमी को दूर करना और विशेष रूप से गरीबों के लिए आवास की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार की गरीबी उन्मूलन कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इंदिरा आवास योजना, एक स्वतंत्र योजना के रूप में जनवरी 1996 में शुरू की गई, लेकिन यह डिजाइन की त्रुटियों, लीकेज, पक्षपात और विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार से त्रस्त थी।

वर्ष 2014 में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में इसके कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां पाई गईं।

संक्षेप में, इंदिरा आवास योजना देश में आवास की कमी के अंतर को काफी हद तक दूर नहीं कर सकी और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में आकलन किए गए आवास की कमी की समस्या लगभग बनी रही।

आईएवाई के तहत स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयास

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में नया रूप दिया गया है। मंत्रालय ने आईएवाई के लंबित आवासों को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्यों को लंबित आईएवाई आवासों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। लंबित आईएवाई आवासों को पूरा करने की स्थिति की केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर समीक्षा की जा रही है। इस निगरानी के परिणाम स्वरूप, 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 43.02 लाख आईएवाई आवासों का निर्माण पूरा हो चुका

है। पीएमएवाई-जी के उत्तरोत्तर सुधारों को आईएवाई आवासों में भी लागू किया गया है, जिससे लाभार्थी अपने लिए अच्छे आवासों का निर्माण कर सकें।

मेरा एक सपना है, जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हों, तो देश के सबसे गरीब के पास अपना पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना नागरिकों के सम्मान से जुड़ा है और इस योजना में यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि अधिक से अधिक महिलाओं, दिव्यांग बहनों और भाइयों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को आवास की सुविधा मिल सके।

- श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

लाभार्थी का नाम: शिव मंगल (छत्तीसगढ़ 1062457)

गांव: कंचापुर

ब्लॉक: बैकुंठपुर

जिला: कोरिया

राज्य: छत्तीसगढ़

अध्याय 2

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण- ग्रामीण निर्धनों के सपनों को साकार करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना

पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजनाओं में कमियों को दूर करने के लिए और वर्ष 2022 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर, इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुर्नगठित किया गया था तथा वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2016 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था।

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

सामाजिक-आर्थिक जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी)-2011 सर्वेक्षण के आवास वंचन डाटा के अनुसार, 2.95 करोड़ लाभार्थियों की पहचान की गई थी जिन्हें मार्च 2022 तक मकान प्रदान किए जाने है। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, 82 लाख परिवारों ने इस अवधि के दौरान या तो अपने मकानों का निर्माण कर लिया है अथवा उन्हें पात्र पाया गया है, जिससे स्थायी प्रतीक्षा सूची में 2.13 करोड़ पात्र लाभार्थी शेष बचे हैं। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 1.92 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई है और 1.36 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

ग्रामीण आवास योजना (आईएवाई+पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन में शुरू किए गए सुधार संबंधी उपायों के परिणामस्वरूप, 7 वर्षों (2014-2021) की समयावधि में 2.10 करोड़ गुणवत्तायुक्त ग्रामीण मकान निर्मित किए गए हैं

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

स्वच्छ खाना बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र सहित न्यूनतम इकाई (मकान) आकार को 20 वर्ग मीटर से बड़ा कर 25 वर्ग मीटर करना।

मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत कार्य योजना जिले।

स्थानीय सामग्रियों और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण करना।

लाभार्थी के पास मानक सीमेंट कंक्रीट के मकान डिजाइनों की तुलना में संरचनात्मक रूप से सुदृढ़, सौंदर्यपूर्ण, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उचित मकान डिजाइनों के व्यापक विकल्प भी उपलब्ध होते हैं।

आवास+ सर्वेक्षण का भी आयोजन किया गया था जिससे पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार उन परिवारों का निर्धारण किया गया था जो पात्र तो हैं परंतु एसएसीसी 2011 में शामिल करने से छूट गए हैं, इस सर्वेक्षण से पीएमएवाई-जी

के अंतर्गत लक्षित 2.95 करोड़ मकानों की सीमा के साथ पात्र परिवारों को स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा।

लाभार्थी का नाम : संजीता बासुमातारी (असम1403057)

गांव : रतनपुर

ब्लॉक : सिसुपानी

जिला : गोमारीगुरी

राज्य : असम

"आवास" से "घर" तक

'शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ और दक्ष ईंधन, तरल और ठोस अपशिष्ट उपचार आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल

- शौचालय को पीएमएवाई-जी आवास का अभिन्न अंग बनाया गया है। आवास को केवल तभी पूरा माना जाएगा जब शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। शौचालय के लिए अन्य योजनाओं के अलावा स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण (एसबीम-जी), मनरेगा के तहत सहायता (12,000/- रुपए) प्रदान की जाती है।
- इकाई सहायता के अलावा मनरेगा के तहत 90/95 श्रम दिवस की अकुशल मजदूरी का प्रावधान है। यह राशि लगभग 18,000/- रुपये होती है।
- विद्युत मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)/सौभाग्य योजना के तहत आवास में बिजली का कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) के माध्यम से एलपीजी का कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किया जाता है।

- जल जीवन मिशन के तहत पाइप से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य योजनाओं के साथ तालमेल

श्रीमती भँवर कंवर का सोलर लाइट, एलपीजी कनेक्शन और शौचालय की सुविधा युक्त घर

पीएमएवाई-जी में अतिरिक्त सुविधा

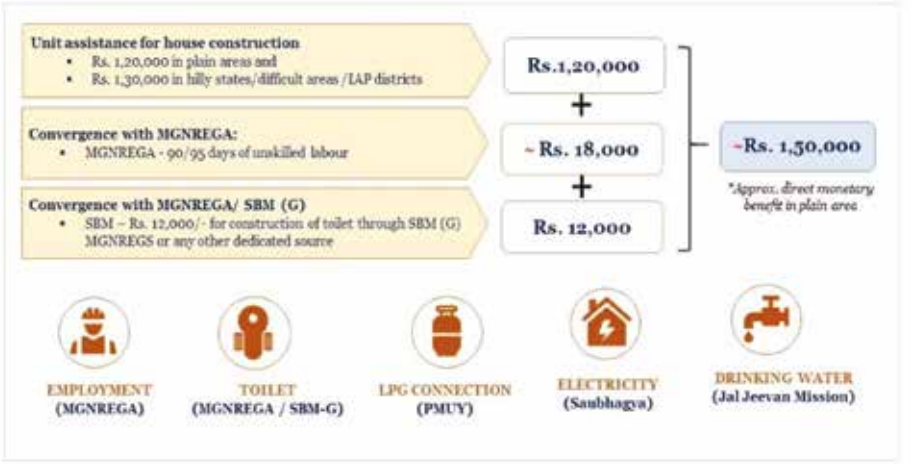

अध्याय 4

लाभार्थियों की पहचान के लिए मजबूत तंत्र

पीएमएवाई-जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता लाभार्थियों के चयन के लिए मजबूत और पारदर्शी तंत्र है

- पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के आवास वंचन मानकों के आधार पर किया जाता है और लाभार्थियों की सूची की वैधता ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाती है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सहायता केवल वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को ही उपलब्ध कराई जाए।
- शून्य, एक, और दो कच्ची दीवारों और कच्ची छत वाले मकानों मे रहने वाले परिवारों को पीएमएवाई-जी के तहत प्राथमिकता दी जाती है।

लाभार्थी जागरूकता और शिकायत निवारण

- ग्राम पंचायत-वार स्थायी प्रतीक्षा सूची को सार्वजनिक भवनों और पंचायत कार्यालयों की दीवारों पर पेंट किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि पात्र परिवारों को उनकी पात्रता की जानकारी है।
- लाभार्थी के चयन में शिकायत, यदि कोई हो, के निवारण के लिए एक अपीलीय प्रक्रिया भी बनाई गयी है।

महिला सशक्तिकरण

- विधवा, अविवाहित और जीवनसाथी से अलग मामले को छोड़कर आवास का आवंटन संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम से किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कुल में से 68 प्रतिशत आवास एकल या संयुक्त रूप से ग्रामीण महिलाओं के नाम से स्वीकृत किए गए हैं।

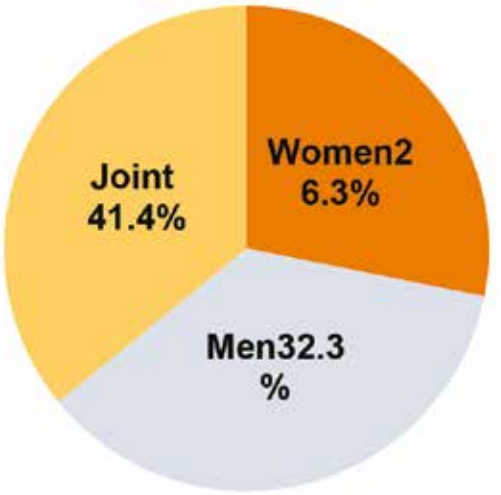

अध्याय 5

गुणवत्तायुक्त निर्माण पर विशेष ध्यान

- अच्छी गुणवत्ता वाले आवासों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके अच्छे आवासों का निर्माण किया जा सके।
- आवासों का निर्माण करने के लिए कुशल राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2021 तक 1.18 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल मानकों के अनुरूप (एनएसक्यू एफ) प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।

Brick Masonry

Leveling of Shuttering

Placing of reinforcement steel

Assessment

- अपने आवास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त डिज़ाइन का चयन करने की सुविधा प्रदान करने के लिए लाभार्थियों को आपदारोधी और स्थानीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल विशेषताओं वाले आवास डिज़ाइन टाइपोलोजी के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

Typology for Zone 'B', Assam

House constructed (typology -Zone 'B', Assam)

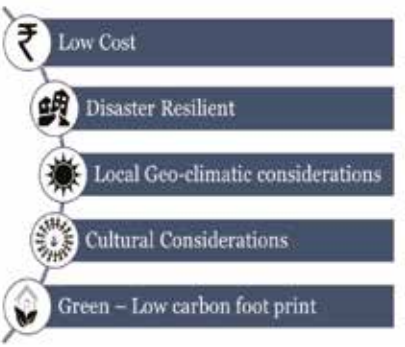

- मंत्रालय द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट मकान डिजाईनों वाले संग्रह 'पहल' का प्रकाशन किया गया है। इसमें 15 राज्यों में 62 आवास डिजाईनों के लिए 108 आवास डिजाईन शामिल है।

House with alternative construction technologies under PMAY-G in the State of Tripura

House with local construction technologies under PMAY-G in the State of Sikkim

साक्ष्य आधारित निगरानी

- मकान के निर्माण के विभिन्न चरणों की जियोटैग्ड तथा टाईम स्टैम्प्ड फोटोग्राफ को वित्तीय सहायता राशि की अगली किश्तों की रिलीज के साथ जोड़ा जाता है।
- प्राप्त की गई फोटोग्राफ को पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता तथा आवासों के पूरा होने की समीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।

लाभार्थियों को सहयोग

- योजना के विषय में लाभार्थियों को प्रेरित करना।
- आवास डिजाइन टाईपोलॉजी की सूची का प्रावधान।
- प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उनके संपर्क विवरण सहित सूची।
- प्रदर्शन के लिए दर्शाए गए मकानों का दौरा।
- आस-पास के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क का ब्यौरा, जो आवास-डिजाइन टाईप की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- मकान के निर्माण में वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों की सहायता करना।

Overnight stay in PMAY-G Houses of Assam

The houses of beneficiaries were not just visited by officials but they spent a night over there

On 11th August 2018 more than 8000 representatives of Assam P&RD Department had meal and stayed in completed PMAY-G houses

This included Hon'ble Ministers, Hon'ble MPs, Hon'ble MLAs, officers and officials, including the grass-root level officials of the department

The houses were selected randomly by computer program. People were motivated to complete the incomplete houses

मकान में बुनियादी सुविधाएं होने और लाभार्थी की उसके पक्के मकान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी से उस स्थान के साथ अपनापन आता है- इसके साथ एक भावात्मक लगाव हो जाता है जो कि मकान को घर में तब्दील कर देता हैं।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं

वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ मकानों का निर्माण

लाभार्थियों के निर्धारण के लिए एसईसीसी-2011 के मकानों से संबंधित आंकड़ों का उपयोग

मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की इकाई सहायता और पर्वतीय राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/आईएपी जिलों में 1,30,000 रुपए

स्वच्छतापूर्वक खाना बनाने के लिए एक समर्पित क्षेत्र सहित 25 वर्ग मीटर की इकाई

लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

बुनियादी सुविधाओं के लिए अन्य कार्यक्रमों के साथ तालमेल – केंद्र एवं राज्य

आवासऐप का उपयोग करते हुए जियो-रेफ्रेंस फोटोग्राफ के माध्यम से निर्माण की प्रगति की निगरानी

आवास डिजाइन टाइपोलॉजी का विकास

गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए राजमिस्त्रि प्रशिक्षण

मकान निर्माण की गुणवत्ता में सुधार तथा इसे समयानुसार पूरा करने पर ध्यान देना

अध्याय 6

साक्ष्य आधारित निगरानी तथा प्रभाव का आकलन।

योजना की निगरानी एमआईएस आवाससॉफ्ट तथा आवास एप, मोबाईल एप्लीकेशन का उपयोग करके एंड-टू-एंड ई-प्रशासन मॉडल के माध्यम से की जाती है।

आवास सॉफ्ट: योजना का ट्रांजेक्शन आधारित एमआईएस

पीएमएवाई-जी के सभी महत्वपूर्ण कार्य, लाभार्थियों के निर्धारण से लेकर मकान के निर्माण से जुड़ी सहायता प्रदान करने तक एमआईएस आवाससॉफ्ट पर किए जाते हैं।
लाभार्थियों के खाते में भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाता है।

आवासएप–एक मोबाईल अनुप्रयोग

बहु-स्तरीय निगरानी

- सामुदायिक भागीदारी से सामाजिक लेखा-परीक्षा
- माननीय सांसदों की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक
- राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता
- केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मी।

प्रभाव आकलन

- 2018-19 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति (एनआईपीएफपी) द्वारा शासन सुधार की मूल्यांकन अध्ययन स्पष्ट करती है कि मकान के निर्माण की औसत दिनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में 314 से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 114 दिन हो गई है।-

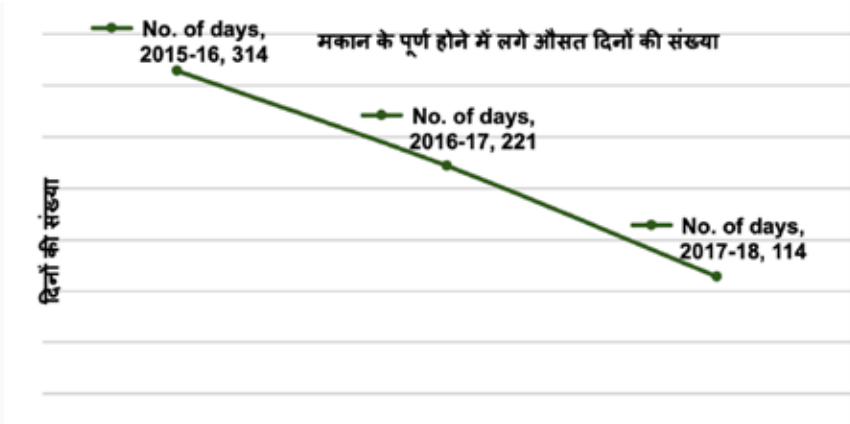

- 2018-19 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति (एनआईपीएफपी) द्वारा शासन सुधार की मूल्यांकन अध्ययन स्पष्ट करती है कि मकान के निर्माण की औसत दिनों की संख्या वित्तीय वर्ष 2015-16 में 314 से घटकर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 114 दिन हो गई है।

लाभार्थी का नाम : सुबिल

ग्राम: मोया

ब्लॉक: बोयरा

जिला: राजगढ़

राज्य: मध्य प्रदेश

कोविड़-19 आपदा के दौरान अतिरिक्त प्रयास

मध्य प्रदेश राज्य में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सितम्बर 2020 में पीएमएवाई- जी के तहत 1.75 लाख नये निर्मित मकानों का उद्घाटन करते हुए कहा कि **महामारी के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत मकानों के पूरा होने की अवधि 125 दिन से घटकर केवल 45-60 दिन हो गई है जो कोरोना वायरस आपदा को अवसर में बदलने का उत्कृष्ट उदाहरण है।**

गरीब कल्याण रोजगार अभियान

महामारी के दौरान शुरु की गई गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर सृजित करके विभिन्न राज्यों मे कई योजनओं को पूरा किया गया है। जीकेआरए पोर्टल के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत कुल 5618.19 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

Narendra Modi
@narendramodi
Replying to @narendramodi
2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तहत तैयार किए गए ये घर इस बात का सबूत हैं कि कोरोना महामारी भी विकास कार्यों में बाधक नहीं बन सकी है।
#PMGraminGrihaPravesh
9:06 PM · Sep 11, 2020 · Twitter for iPhone

अध्याय 8

सफलता की कहानियां

1 : शशि बारिक ने कोविड़-19 महामारी के दौरान अपने घर का निर्माण करवाया

कोविड़-19 के कारण जब देश में पूर्ण लॉकडाउन था उस समय शशि बारिक ने पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत अपने मकान के निर्माण का निर्णय किया। अप्रत्याशित लॉकडउन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने श्रमशक्ति और निर्माण समाग्री को एकत्रित करने का पूर्ण प्रयास किया। जिसके फलस्वरुप शशि बारिक ने प्रथम किश्त प्राप्त करने के एक माह के भीतर मकान का निर्माण पूर्ण कर लिया

लाभार्थी: शशि बारिक (ओआर4160180),जिला, बालनगीर, ओड़िशा

80 वर्षीय विधवा शशि बारिक, जो बालनगीर जिले मे लुईसिंगा ब्लॉक में हीरापुर ग्राम पंचायत के टेभाडुंगुरी गाँव मे एक जर्जर मकान में रहती थी, कहती है "अब हम खुशी से सीमेंट कंकरीट वाले मकान में रह रहे हैं। हमारे जैसे गरीब परिवारो को पक्का मकान बनाने मे सहायता करने के लिए सरकार का धन्यवाद। अब हम इस मकान के गर्वान्वित मालिक है।"

उसका बेटा दैनिक मजदूर है। अपनी छोटी सी कमाई से वह 5 सद्स्यीय परिवार के लिए दो वक्त के भोजन का इंतजाम कर पाता है। पक्का मकान हमेशा से उनके लिए एक सपना था। किन्तु सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्का मकान के निर्माण के लिए 130,000/- रु. की वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी सहायता की। समय से पूर्व मकान निर्माण के लिए शशि को सरकार की तरफ से 20,000 रु. की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

2 : छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावी क्षेत्र की कहानी

जिला – बस्तर

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पक्के आवास से बदली जिंदगी

सबका साथ-सबका विकास, छत्तीसगढ़ शासन का जनता से किया यह वादा बुधराम कश्यप निवासी ग्राम पंचायत तोतर, जिला बस्तर के लिए जीवंत हो उठा। ग्राम पंचायत तोतर, बस्तर जिले के दुर्गम क्षेत्र में बसा हुआ है, लाल आतंक के साए में घुटी-घुटी सी जिंदगी जीने वाले बुधराम कश्यप के कानों में जब भी छत्तीसगढ़ शासन के नारे सबका साथ-सबका विकास की गुंज पड़ती वह सोचता विकास की यह बातें उसके और उसके जैसे आदिवासियों के लिए नहीं हैं, उसे लगता ऐसे धुर नक्सली क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, हमारी जिंदगी तो बस यूँ ही अभावों के साथ अपने अंत तक पहुँच जाएगी। पर जनता के विकास का शासन का यह वादा पक्का था, रोजी-मजदूरी करके अपना परिवार चलाने वाले बुधराम कश्यप को प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान की स्वीकृति मिली, बुधराम की आंखों के सामने ही उसके अनदेखे सपने ने आकार लेना शुरू किया, बुधराम के घर में मनरेगा योजना से शौचालय का भी निर्माण किया गया। इस परिवार को उज्जवला योजना से गैस चूल्हा भी प्रदान किया गया और देखते ही देखते बुधराम कश्यप और उनके परिवार की तस्वीर बदलने लगी, अब यह परिवार पक्के मकान में सुख-चैन से रहता है, घर में बने शौचालय ने जैसे इस परिवार की शान बढ़ा दी है। अब जब बुधराम कश्यप को चाय पीनी होती है तो पत्नी को आवाज देते ही कुछ ही

पलों में चाय का प्याला उनके हाथ में होता है, आखिर धर्मपत्नी को चूल्हे की आग ताजा करने में वक्त जो नहीं लगता, अब उनकी चाय गैस पर जो बनती है। वनों से घिरे दुर्गम, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कश्यप की जन-हितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लोगों के जीवन की तस्वीर बदलने लगी है और लोगों का विश्वास और भी बलवंत होने लगा है कि विकास की इस धार में कोई भी पीछे नहीं छूटेगा, सबके साथ से सबका विकास अवश्य ही होगा।

3 : बंधना औरांव का सपना साकार हुआ

गुमला जिले के सुदूर घाघरा ब्लॉक के ग्राम चपका निवासी 59 वर्षीय बंधना औरांव एक कमरे के कच्चे मकान में रह रहा था। उसके परिवार को विशेषकर बारिश और सर्दी के मौसम में कच्चे मकान में रहने से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस मौसम के दौरान उसके बच्चे बीमार हो जाते थे और गरीबी के कारण दवाओं की व्यवस्था करना उसके लिए बहुत मुश्किल था।

ऐसी खराब स्थिति में, पक्के मकान का निर्माण ही बंधना का एक सपना था। यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कारण ही यह सपना साकार हो पाया।

बंधना ने परिवार के सदस्यों की मदद से अपना मकान बनाया। निर्माण सामग्री की व्यवस्था करने में आवास मित्र ने भी उसका साथ दिया। बंधना अब अपने परिवार के साथ अपने नए घर में रह रहा है। वह अब किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए खुश और आश्वस्त है। वह पक्के मकान का मालिक है और इसने समाज में उसका ओहदा बढ़ाया है। वह अब गांव में अन्य लोगों को न्यूनतम समय अवधि में मकान निर्माण कार्य पूरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

Before

After

अध्याय 9

मीडिया गैलरी

Ministry of Rural Development... · Feb 3

"2022 तक सबके लिए आवास" के लक्ष्य की ओर अग्रसर भारत सरकार ने आज "प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण" #PMAYG के तहत 2 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण आवास बना कर एक नया इतिहास रचा है।

#HarKadamAtmanirbhar #TransformingIndia

Ravi S Singh

Tribune News Service

New Delhi, September 12

Prime Minister Narendra Modi on Saturday said the Centre's drive for integrated development of villages and rural areas in the country would be further intensified.

Launching the newly constructed 1.75 lakh houses under PMAY-G - a Central scheme - in Madhya Pradesh through video conference, Modi said development of villages and empowerment of the poor through welfare schemes would strengthen India.

Amit Shah
@AmitShah

पीएम आवास योजना गरीबों को समाज में सम्मान व गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत पीएम मोदी जी का लक्ष्य है, इसी सपने को साकार करने की दिशा में मोदी सरकार दिन-रात प्रयासरत है। #PMGraminGrihaPravesh

Translate Tweet

12:44 PM · Sep 12, 2020 · Twitter for iPhone

3.2K Retweets **143** Quote Tweets **22.8K** Likes

ISRO @isro · Sep 14

Hon'ble PM @narendramodi inaugurated1.75 lakh houses in Madhya Pradesh under #PMAYGramin #PMGraminGrihaPravesh

Ministry of Rural Development, Government o... · Sep 12

#PMAYGramin has implemented evidence-based monitoring wherein for each house a minimum of 5 geo-tagged time stamped photographs are captured and plotted on a digital map. This enables micro level planning and promotes the principle of transparency. #PMGraminGrihaPravesh

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार